हुई। आज राजस्थान को थोड़ा गेहूं देने के अलावा कुछ भी नहीं देना है, बल्कि राजस्थान से लेकर दूसरे इलाकों को देना है।

AMENDMENT OF HINDU SUCCESSION ACT
*608 SHRI RANDHIR SINGH Will

- *608. SHRI RANDHIR SINGH: Will the Minister of LAW be pleased to state:
- (a) whether Government have received any fresh proposals from the various State Governments suggesting amendment in the Hindu Succession Act so that daughters could have share in the property of their husbands rather than in the property of their father and brothers; and
- (b) if so, the reaction of Government thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW (SHRI M. YUNUS SALEEM): (a) No such proposal has been received, Sir.

(b) Does not arise.

श्री रणधीर सिंह: क्या यह सही है कि पंजाब गवर्नमेंट और हिरयाणा गवर्नमेंट ने जो एसेम्बली तोड़ दी गई है,....

MR. SPEAKER: This is question hour. Let him ask about daughters not about the Assembly.

भी रणधीर सिंह: क्या यह सही है कि गवर्नमेंट के पास पंजाब गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ़ से यह प्रोगोजन आया है और जो असम्बली तोड़ दी गई है, उसका युनेनिमस रेजोल्यू शन गवर्नमेंट के पास पहुंचा है, जिसमें कहा गया है कि हरियाणा में जिस तरह हमेशा से लड़की को ससुर की तरफ से ही हक मिलता था, अब भी उधर से ही हक मिलना चाहिय और उसको उसके बाप की जायदाद में से हक नहीं मिलना चाहिए; अगर हां, तो क्या गवर्नमेंट उस पर गीर कर रही है या नहीं?

THE MINISTER OF LAW (SHRI GOVINDA MENON): No proposal was received from the Government of Haryana on this matter. But I can say for the information of the House that a resolution was moved in the Punjab Legislative

Assembly requesting the Punjab Government to move the Union Government to amend the Hindu Succession Act in such a way as to make the daughter inherit the property of the father-in-law after her marriage instead of that of her father. Though the resolution was passed in the Assembly, it was rescinded a few days later by a motion moved by the Chief Minister. A committee was appointed by the Punjab Government to go into the matter and a report has been submitted by it to the State Government. We have received a copy of the report with a request that the contents may be kept confidential.

श्री रणधीर सिंह: जब से मनु महाराज ने राष्ट्र के लिए हमारे समाज का सब से पुराना और सब से शानदार कानून बनाया, उसी व्यक्त से, हजारों सालों से, अगर सारे देश में नहीं, तो शुमाली हिन्दुस्तान में, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-काश्मीर, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में, रिवाज का यह कानून चला आता है—रिवाज का कानून तहरीरी कानून से ज्यादा मजबूत और पक्का होता है— कि लड़की को अपने ससुर की जायदाद में हक मिले, अपने बाप की जायदाद में नहीं।

MR. SPEAKER: You are converting it into a joke; daughters are suffering because of your joke. This is not a debate on daughter's property. This is question hour. Put a supplementary.

श्री रणधीर सिंह: आज-कल हरियाणा में एसेम्बली नहीं है, इसलिए आप मुझे कुछ कहने की इजाजत दीजिए। में आपके जरिये ढाई करोड़ आदिमयों की आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहता हूं। हम से चाहे कितना ही टैक्स ले लिया जाये, लेकिन मेहरबानी कर के लड़की को बहू बना कर अपने गांव में न रखने दें। क्या आप समझते हैं या नहीं? आप भी किसान हैं। आपने मेरी बात समझ ली है। में आपकी मार्फत मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि वह कब ढाई करोड़ आदिमयों की आवाज, किसानों की आवाज, सिर्फ हरियाणा नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान

के लोगों की आवाज को सुनेंगे कि लड़की को सिर्फ उस के ससुर की जायदाद में हक मिलना चाहिए और कब इस बारे में कानून पास करेंगे। मैं इस बारे में लिमिट चाहता हूं।

SHRI GOVINDA MENON: I hope the member is aware that after protracted discussions in Parliament, the Hindu Code Bills were passed. Under the Hindu Succession Act, the daughter and the son have been given equal rights in the father's property. Government continue to think that that is the proper law with respect to this matter.

श्री रणबीर सिंह : क्या गवर्नमेंट उस कानून में तरमीम करना चाहती है; अगर हां, तो वह कब तरमीम करेगी?

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री: अध्यक्ष महोदय, में मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खेती की भूमि के सम्बन्ध में इस कानून के लागू होने के पश्चात् क्या कुछ व्यावहारिक कठिनाई उन के [सामने या उन की नोटिस में आई है खास तौर से जब कि खेती की सम्पत्ति बहुत छोटी-छोटी मिल्कियतों में बंट गई है तो उस में इस प्रकार दोनों जगह सम्पत्ति का बंटवारा होने से जो खेती पर भी कुप्रभाव पड़ेगा और उत्पादन पर भी कुप्रभाव पड़ेगा और उस को देखते हुए वह इस कानून में कोई उचित परिवर्तन करने की तरफ ध्यान देंगे ?

SHRI GOVINDA MENON: For the information of the member and the House, I would point to a provision in the Hindu Succession Act which says that whatever be the provision under the law, it shall not affect any law in any State preventing fragmentation of holdings. There is today in force a law known as the Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act of Bombay. I think the proper remedy is for other States also to have legislations of this type to prevent fragmentation.

L96LSS/67-2

SHORT NOTICE QUESTION SHORTAGE OF SPIRIT IN DELHI

S.N.Q. 12. SHRI KANWAR LAL GUPTA:

SHRI M. L. SONDHI:

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that there is a great shortage of spirit in Delhi;
- (b) whether it is also a fact that Delhi did not receive its November quota so far and no fresh quota has been allotted for the next month;
- (c) if so, the reasons for the shortage; and
- (d) the steps taken by Government to remove the shortage of spirit in the capital?

THE MINISTER OF PETRO*LEUM AND CHEMICALS AND SOCIAL WELFARE (SHRI ASOKA MEHTA): (a) Yes, Sir.

- (b) Delhi receives its supplies of spirit from U.P. subject to availability. Supplies for November 1967 were delayed but have since been received. Allocation from U.P. for December 1967 has also been received and arrangements to lift the supplies are being made.
- (c) There is an acute shortage of spirit in the country on account of reduced availability of molasses which in turn is due to a fall in the production of white sugar.
- (d) Delhi Administration have rationed the supply of spirit with a view to meet the requirements of hospitals and doctors on a priority basis and to the maximum extent possible. They are also tapping sources of supply other than U.P.

भी कंबर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली का जो कोटा 50 हजार गैलन का था एक महीने में वह अब काट कर के 15 हजार गैलन कर दिया । नतीजा यह हुआ कि कई अस्पतालों में भी डाक्टर मरीजों को चिट लिखते हैं कि पहले आप स्पिरिट से आइए तब आप को दवाई दी जायगी और इसके